

डिजिटल ट्रस्ट

सुरक्षित और समावेशी ई-गवर्नेंस की आधारशिला

संपादित : मोहन दास विस्वम्

भारत के विशाल और विविध समाज में विश्वास हमेशा से लोगों और संस्थानों के बीच अदृश्य पुल रहा है। डिजिटल युग में इस पुल का नया नाम है—डिजिटल ट्रस्ट।

अब यह केवल कुशल शासन का परिणाम नहीं, बल्कि हर डिजिटल संवाद की नींव बन गया है। विश्वास के बिना सबसे उन्नत प्लेटफॉर्म भी नागरिकों से जुड़ने में विफल हो जाते हैं; पर विश्वास के साथ, एक साधारण क्लिक भी आत्मविश्वास का प्रतीक बन जाता है—ऐसा मौन मत जो सुनने, सुरक्षा देने और सेवा करने वाले शासन के पक्ष में जाता है।

डिजिटल ट्रस्ट ही वह भावना है जो बुंदेलखंड के एक ग्रामीण को बिना डर डिजिटल खता खोलने का भरोसा देती है, कश्मीर का एक छात्र ऑनलाइन छात्रवृत्ति आवेदन कर पाता है, और पुणे का एक रोगी अपने डॉक्टर के साथ सुरक्षित रूप से मेडिकल रिकॉर्ड साझा करता है। यह वह शांत विश्वास है कि तकनीक केवल उपकरण नहीं, बल्कि अधिकारों की संरक्षक है।

ई-गवर्नेंस: पहुँच से भरोसे तक की यात्रा

भारत में ई-गवर्नेंस की शुरुआत एक वादे से हुई थी—शासन को प्रभावी, उत्तरदायी और सुलभ बनाने के वादे से। पिछले एक दशक में यह वादा डिजिटल इंडिया पहल के माध्यम से व्यवहार में बदला है।

आधार, उमंग, डिजिटल, ई-कोर्ट्स और माईगव जैसे प्लेटफॉर्मों ने सार्वजनिक सेवा वितरण को नई परिभाषा दी है। मोबाइल-फर्स्ट और क्लाउड-फर्स्ट दृष्टिकोण के साथ ई-क्रांति मिशन ने सरकारी सेवाओं को नागरिकों की उंगलियों तक पहुँचा दिया है। भीम और यूपीआई जैसी पहल ने डिजिटल भुगतान को दैनिक जीवन का हिस्सा बना दिया है, जिससे लाखों लोगों को सशक्त किया गया है और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिला है।

आज भारत संयुक्त राष्ट्र के ई-गवर्नेंस विकास सूचकांक में अग्रणी देशों में शामिल है—यह इस बात का प्रमाण है कि डिजिटल शासन अब सुविधा से आगे बढ़कर सामाजिक समानता का साधन बन गया है। फिर भी चुनौतियाँ बनी हुई हैं—साइबर खतरों से लेकर



डिजिटल ट्रस्ट भारत की ई-गवर्नेंस क्रांति की आधारशिला है। यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक डिजिटल अंतःक्रिया—चाहे वह स्वास्थ्य सेवा, वित्त या भूमि प्रबंधन में हो—सुरक्षित, पारदर्शी और नैतिक हो। मजबूत साइबर सुरक्षा, गोपनीयता संरक्षण और जवाबदेही ढाँचों को एकीकृत करके सरकार नागरिकों और संस्थानों दोनों के बीच विश्वास का निर्माण करती है। जैसे-जैसे एआई और ब्लॉकचेन जैसी उभरती प्रौद्योगिकियाँ शासन व्यवस्था को नया रूप दे रही हैं, विश्वास ही प्रगति का वास्तविक मापदंड बना रहेगा। भविष्य के लिए तैयार डिजिटल भारत की पहचान उसके सिस्टम की गति से नहीं, बल्कि उसके नागरिकों द्वारा उनमें रखे गए विश्वास से होगी—यह शांत आश्वासन कि प्रौद्योगिकी ईमानदारी के साथ सेवा करती है।



सीमित डिजिटल साक्षरता और दूरदराज क्षेत्रों में कनेक्टिविटी की कमी तक। इन चुनौतियों का समाधान केवल तकनीक में नहीं, विश्वास में निहित है—यह विश्वास कि प्रणालियाँ सुरक्षित हैं, डेटा का सम्मान किया जाता है, और हर नागरिक को देखा और समझा जाता है।

डिजिटल ट्रस्ट की परिभाषा

विश्व आर्थिक मंच डिजिटल विश्वास को इस अपेक्षा के रूप में

परिभाषित करता है कि डिजिटल प्रौद्योगिकियाँ और सेवा प्रदाता जिम्मेदारी से कार्य करेंगे, हितधारकों के हितों की रक्षा करेंगे और सामाजिक मूल्यों को बनाए रखेंगे। सरल शब्दों में, यह विश्वास है कि डिजिटल दुनिया अपने उपयोगकर्ताओं के साथ विश्वासघात नहीं करेगी।

आईएसओ/आईईसी 38505 जैसे मानक नैतिक और जवाबदेह डेटा प्रबंधन की वकालत करते हैं, जबकि भारत का डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, 2023 व्यक्तिगत सूचना की सुरक्षा को मजबूत करता है।

संस्थानों के लिए, डिजिटल ट्रस्ट केवल अनुपालन नहीं—चरित्र का प्रतीक है। नागरिकों के लिए, यह आश्वासन है कि उनकी पहचान, जानकारी और गरिमा सुरक्षित है।

डिजिटल ट्रस्ट के स्तंभ सुरक्षा

विश्वास की नींव संरक्षण से शुरू होती है। मजबूत एन्क्रिप्शन, सुरक्षित भंडारण और बहु-कारक प्रमाणीकरण यह सुनिश्चित करते हैं कि नागरिकों का डेटा अभेद्य बना रहे। निरंतर निगरानी और वास्तविक समय में खतरे की प्रतिक्रिया उल्लंघनों के विरुद्ध सरकार की डिजिटल ढाल का निर्माण करती है।

डेटा संरक्षण

नागरिकों को यह भरोसा होना चाहिए कि उनका डेटा सावधानी और सहमति के साथ उपयोग किया जा रहा है। पारदर्शी नीतियाँ और जिम्मेदार डेटा प्रबंधन गोपनीयता को विशेषाधिकार नहीं, बल्कि अधिकार बनाते हैं।

विश्वसनीयता

जब सेवाएँ विफल नहीं होतीं, तब नागरिकों का विश्वास बढ़ता है। विश्वसनीय प्रणालियाँ—जो अधिक लोड में भी बाधित नहीं होतीं और प्रमाणपत्र, भुगतान तथा रिपोर्ट समय पर प्रदान करती हैं—स्वयं शासन व्यवस्था में विश्वास का निर्माण करती हैं।

निष्पक्ष उपयोगकर्ता सहभागिता

डिजिटल सेवाएँ निष्पक्ष, पक्षपात-रहित और समावेशी होनी चाहिए। जैसे-जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता निर्णय-निर्माण में बड़ी भूमिका निभा रही है, वैसे-वैसे शासन में प्रयुक्त एल्गोरिदम मानव नैतिकता के प्रति जवाबदेह बने रहना चाहिए।

पारदर्शिता

जब नागरिक समझते हैं कि उनका डेटा कैसे उपयोग होता है, तो अविश्वास मिट जाता है। खुले डैशबोर्ड, पारदर्शी नीतियाँ और स्पष्ट संवाद संदेह को विश्वास में बदल देते हैं।



सविता भटनागर
वरिष्ठ तकनीकी निदेशक
savita.bhatnagar@nic.in

जवाबदेही

एक विश्वसनीय डिजिटल सरकार अपनी सफलताओं के साथ-साथ अपनी त्रुटियों की भी जिम्मेदारी लेती है। स्पष्ट जवाबदेही, ईमानदार रिपोर्टिंग और नैतिक सुधारात्मक उपाय संस्थानों की विश्वसनीयता को सुदृढ़ करते हैं।

तकनीक

ब्लॉकचेन, जीरो-ट्रस्ट सिक्वोरिटी, एआई-आधारित खतरा पहचान और विकेन्द्रीकृत पहचान जैसी उभरती तकनीकें शासन के भविष्य को आकार दे रही हैं। आने वाले कल के नागरिक न केवल डिजिटल प्रणालियों का उपयोग करेंगे, बल्कि उन पर विश्वास भी

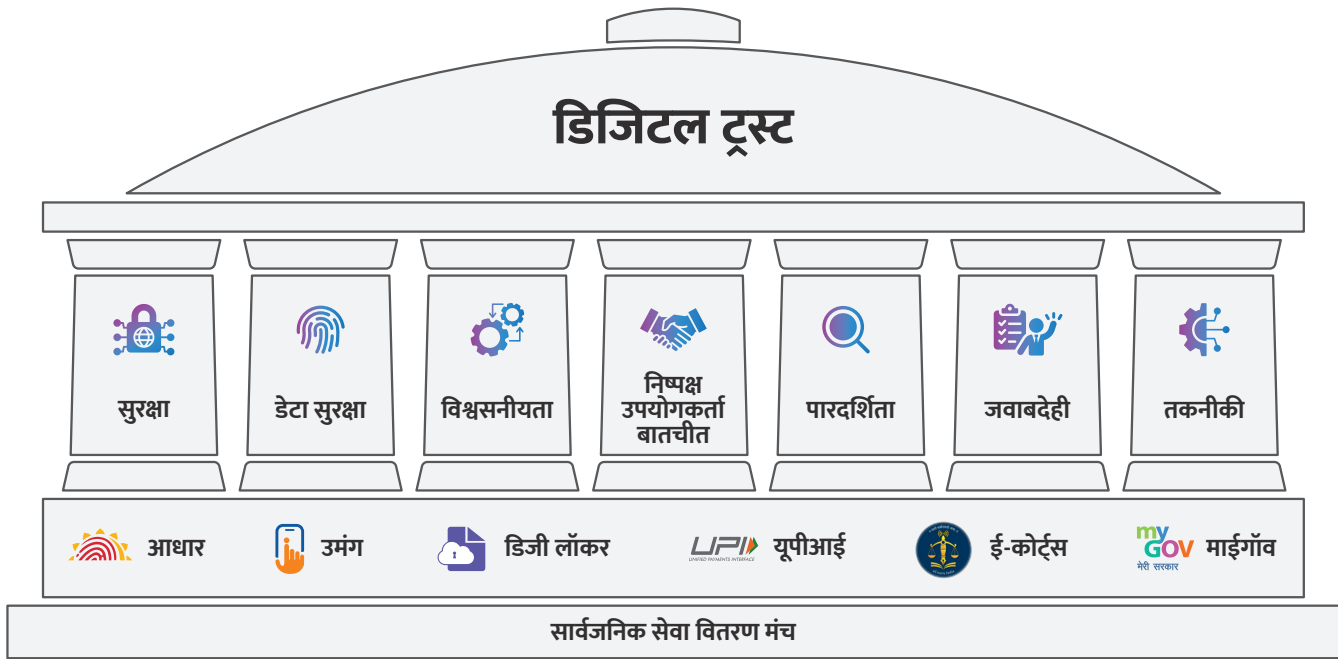
नहीं है—यह गरिमा से जुड़ा हुआ है। एन्क्रिप्टेड स्वास्थ्य अभिलेख, ब्लॉकचेन-आधारित ई-सहमति प्रणालियाँ और जीरो-ट्रस्ट आर्किटेक्चर यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्येक मरीज की जानकारी गोपनीय, अनुरेखणीय और छेड़छाड़-रोधी बनी रहे। डिजिलॉकर और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जैसे एकीकृत प्लेटफॉर्म नागरिकों को उनके चिकित्सीय डेटा पर नियंत्रण प्रदान करते हैं—जिससे वे यह तय कर सकें कि क्या साझा करना है, कब साझा करना है और किसके साथ साझा करना है।

जब कोई मरीज कोई रिपोर्ट अपलोड करता है या ई-प्रिस्क्रिप्शन प्राप्त करता है, तो यह केवल एक डिजिटल क्रिया नहीं होती—यह प्रणाली में विश्वास का एक संकेत होता है। नैतिक एआई-आधारित

अपारदर्शिता और हेरफेर से मुक्त होकर। प्रत्येक सत्यापित अभिलेख निभाए गए एक वादे के समान है। हर लेन-देन को सत्यापन योग्य सत्य से जोड़कर, डिजिटल विश्वास भूमि प्रशासन को एक पारदर्शी, सुलभ और भ्रष्टाचार-मुक्त प्रणाली में बदल रहा है—एक ऐसी नींव, जहाँ नागरिक केवल भूमि के मालिक ही नहीं रहते, बल्कि स्वामित्व की अखंडता पर भी विश्वास करते हैं।

अग्रिम राह

ई-गवर्नेंस का अगला दशक इस बात से नहीं तय होगा कि सेवाएँ कितनी तेज हैं, बल्कि इस बात से कि वे कितनी विश्वसनीय हैं। गति तकनीकी है; विश्वास मानवीय।



करेंगे—क्योंकि वे प्रणालियाँ सत्यापन योग्य, पारदर्शी और डिज़ाइन द्वारा सुरक्षित होंगी।

नीतिगत और संस्थागत समर्थन

भारत का नीतिगत परिदृश्य अब डिजिटल ट्रस्ट की नैतिकताओं के अनुरूप ढल रहा है। डी.पी.डी.पी. अधिनियम (2023) नागरिकों को अपने व्यक्तिगत डेटा पर नियंत्रण देता है। राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र अपने सुरक्षित डेटा सेंटर्स और क्लाउड सेवाओं के माध्यम से प्रतिदिन लाखों डिजिटल लेन-देन की अखंडता बनाए रखता है।

अब आवश्यकता है एक डिजिटल ट्रस्ट चार्टर की—ऐसा संस्थागत संकल्प जो हर मंत्रालय को यह सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित करे कि स्वास्थ्य से शिक्षा तक, हर सरकारी सेवा गोपनीयता, पारदर्शिता और समावेशिता के सिद्धांतों पर आधारित हो। यह चार्टर केवल तकनीकी प्रगति का नहीं, बल्कि नैतिक परिपक्वता का प्रतीक होगा।

विश्वास की मिसालें

स्वास्थ्य सेवा: जहाँ डेटा मिलाता है गरिमा से

स्वास्थ्य सेवा में डिजिटल विश्वास केवल सुरक्षा तक सीमित

निदान और सुरक्षित टेलीमैडिसिन नेटवर्क गोपनीयता और सहमति को बनाए रखते हुए देश के दूर-दराज क्षेत्रों तक देखभाल का विस्तार करते हैं। मिलकर, ये प्रणालियाँ एक रोगी-केंद्रित पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करती हैं, जहाँ प्रौद्योगिकी स्वास्थ्य और मानवता—दोनों की रक्षा करती है, और यह सिद्ध करती है कि विश्वास भी दवा जितनी ही प्रभावी ढंग से उपचार कर सकता है।

भूमि अभिलेख प्रबंधन: पारदर्शिता में निहित विश्वास

लाखों भारतीयों के लिए भूमि स्वामित्व लंबे समय से गर्व और जोखिम—दोनों का प्रतीक रहा है। ब्लॉकचेन रजिस्ट्रियों और छेड़छाड़-रोधी डिजिटल लेजर अब इस कहानी को नए सिरे से लिख रहे हैं—जो संपत्ति अभिलेखों में पारदर्शिता, स्थायित्व और निष्पक्षता ला रहे हैं। जीआईएस मैपिंग, एआई-आधारित सत्यापन और सुरक्षित क्लाउड भंडारण से जुड़े ये सिस्टम धोखाधड़ी को रोकते हैं, विवादों को कम करते हैं और भूमि शासन में विश्वास को पुनर्स्थापित करते हैं।

आज बिहार का कोई किसान या बेंगलुरु का कोई खरीदार एक ही क्लिक में स्वामित्व की पुष्टि कर सकता है—बिचौलियों,

एक विश्वसनीय डिजिटल सरकार गोपनीयता और नैतिकता का सम्मान करते हुए तेज, अधिक व्यक्तिगत सेवाएँ प्रदान करेगी। यह शासन को नियंत्रण की प्रणाली से विश्वास की संस्कृति में परिवर्तित करेगी।

इस परिवर्तन के संरक्षक के रूप में हम—प्रौद्योगिकीविद्, नीति-निर्माता और नागरिक—यह याद रखें कि डिजिटल विश्वास एक बार बनकर पूरा नहीं हो जाता; इसे हर दिन निर्मित किया जाता है।

प्रत्येक सुरक्षित लॉगिन, प्रत्येक पारदर्शी प्रक्रिया, प्रत्येक ईमानदार प्रतिक्रिया—ये वे छोटे कार्य हैं जो भारत के डिजिटल लोकतंत्र को परिभाषित करेंगे। और जब विश्वास शासन की डिफॉल्ट व्यवस्था बन जाएगी, तब प्रौद्योगिकी केवल लोगों की सेवा ही नहीं करेगी—वह उनकी अपनी बन जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें

सविता भटनागर

वरिष्ठ तकनीकी निदेशक

सॉफ्टवेयर विकास इकाई, एनआईसी पुणे

114, गणेशखिंड रोड, आईसीएस कॉलोनी, अशोक नगर

पुणे, महाराष्ट्र - 411007

ईमेल: savita.bhatnagar@nic.in, फ़ोन: 011-243038576